स्टार्टअप में हैं अनंत संभावनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमें उद्यमिता क्रांति और इनोवेशन की तरफ तेजी से बढ़ना ही होगा।

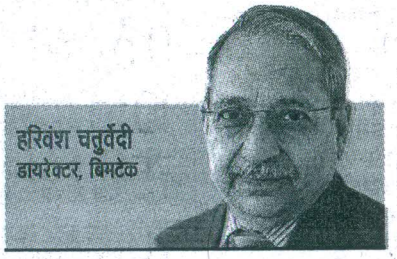

हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की, तो देश की युवा-पीढ़ी में अपने भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद बंधी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम को देश के 350 जिलों व शीर्ष विश्वविद्यालयों में लाइव दिखाया गया। इससे उम्मीद बनी है कि आने वाले महीनों में उद्यमिता, इनोवेशन और उससे जुड़े कारोबार में तेजी आएगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्टार्टअप आंदोलन भारत के लिए नया नहीं है। नई स्टार्टअप नीति से फर्क यह पड़ेगा कि युवा उद्यमियों के सामने आ रही मुश्किलों का न केवल कुछ हल निकलेगा, बल्कि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों व प्रबंध संस्थानों से निकल रहे लाखों युवाओं में उद्यमी बनने के लिए नई प्रेरणा पैदा होगी। 15 अगस्त, 2015 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 'स्टार्टअप इंडिया-स्टैंडअप इंडिया' का नारा दिया था। तभी से औद्योगिक नीति विभाग में स्टार्टअप नीति बनाने पर विचार-मंथन चल रहा था। वैसे एनडीए सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षों में 'मेक-इन-इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भरसक कोशिश की, पर अभी तक के परिणाम आशाजनक नहीं रहे हैं। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी ने भारत के निर्यात पर बुरा असर डाला है। इससे कई निर्यातोन्मुख उद्योगों में उत्पादन घटा है और रोजगार के अवसर कम हुए हैं। सरकार के सामने यक्ष-प्रश्न है कि अगले आम चुनाव, यानी वर्ष 2019 के पहले किस तरह करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाएं। यह आसान नहीं है। सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।

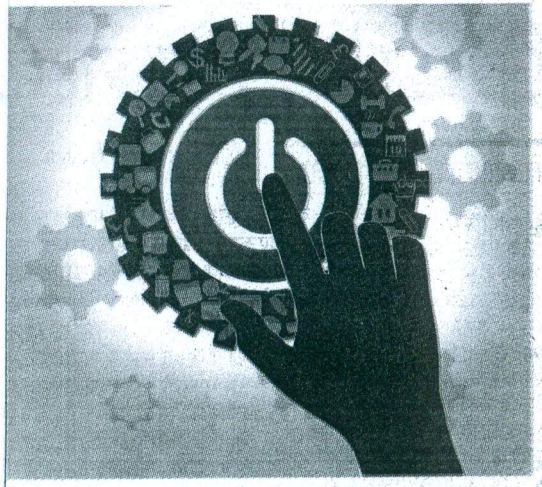

चित्रांकन: डी. श्रीनिवास

सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में हजारों स्टार्टअप उठ खड़े हों और लाखों युवाओं को उनमें रोजगार मिल सके। पूरी दुनिया में इस समय जो उद्यमिता की लहर चल रही है, उसमें भारत भी एक बड़ा दावेदार है। नैसकॉम और जिनोव कंसल्टिंग के सर्वेक्षण बताते हैं कि दुनिया में स्टार्टअप शुरू करने की दौड़ में फिलहाल भारत तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका व ब्रिटेन हैं। भारत में फिलहाल स्टार्टअप की संख्या लगभग 4,200-4,400 है, जबकि अमेरिका में 47,000-48,000 स्टार्टअप चल रहे हैं और ब्रिटेन में इनकी तादाद करीब 5,000 है। अगले साल तक भारत उसे पीछे छोड़ सकता है। भारत में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की औसत आयु 28 वर्ष है। रोजाना तीन-चार स्टार्टअप स्थापित होते हैं। भारत के 4,200-4,400 स्टार्टअप में करीब 35,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। युवा उद्यमियों को स्टार्टअप पर दिशा-निर्देश देने के लिए देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम के जो केंद्र काम कर रहे हैं, उनकी तादाद करीब 120 है। फिलहाल भारतीय स्टार्टअप में लगभग 85,000 लोगों को रोजगार मिला है।

क्या स्टार्टअप आंदोलन भारत में उद्यमिता क्रांति को जन्म दे सकता है? क्या इससे रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा हो सकते हैं? यह इस पर निर्भर करेगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कितना आगे आती हैं? स्टार्टअप आंदोलन के एक बड़े समर्थक टीवी मोहनदास पई (चेयरमैन, मनीपाल ग्लोबल एजुकेशन) का कहना है कि अगले 10 वर्षों में देश में एक लाख स्टार्टअप स्थापित होंगे। ये 35 लाख रोजगार पैदा करेंगे और उनका कुल कारोबार 3,50,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग इस भविष्यवाणी से आश्वस्त न हों, लेकिन यह कोरी कल्पना भी नहीं है। नई तकनीक के कारण दुनिया भर में जो उथल-पुथल चल रही है, उसे हम अमेरिका के डिट्रोइट शहर से समझ सकते हैं। यह कभी ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र था, आज यह भुतहा शहर बन चुका है। दुनिया में आज 'फ्रिक्शनलेस अर्थव्यवस्था' की चर्चा है, जिसमें कंपनियों के लिए जरूरी नहीं कि वे अथाह भौतिक संपत्तियों (मशीन, फैक्टरी, स्टॉक आदि) को इकट्ठा करें। गूगल, फेसबुक, उबर, लिफ्ट, एअर बीएनबी और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भौतिक संपत्तियों का अंबार लगाए बिना दुनिया भर में छा गई हैं। भारत में पांच-सात वर्ष पहले हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिन्त्रा, पेटीएम, ओला कैब्स, जैसे स्टार्टअप को नहीं जानते थे। आज ये कंपनियां 20-25 वर्ष पुरानी कंपनियों से कहीं बेहतर कारोबार कर रही हैं। इन्हें पूरी दुनिया से निवेश भी मिल रहा है।

लेकिन कामयाबी की इन कहानियों के बावजूद इन उद्यमियों की कुछ समस्याएं भी हैं, जिनके कारगर हल सरकार को ढूंढ़ने होंगे। सबसे बड़ी समस्या कारोबार को आसानी से शुरू न कर पाने की है। भारत सरकार के औद्योगिक नीति विभाग ने कारोबार शुरू करने की सहूलियत बढ़ाने के लिए कोशिश जरूर की है, किंतु अब भी अलग-अलग सरकारी विभागों से अनुमति लेना और उन्हें 'प्रसन्न' रखना उद्यमियों के लिए टेढ़ी खीर है। स्टार्टअप उद्यमी कर-प्रणाली से भी परेशान हैं, जिसके कारण उन्हें विदेश में जाकर अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड करानी पड़ती हैं। स्टार्टअप उद्यमियों की सबसे बड़ी शिकायत कंपनियों में होने वाले विनियोग पर पूंजी लाभ टैक्स का लगाया जाना है। एंजेल इन्वेस्टरों से फंड लेने पर उन्हें 33 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। इसलिए भारतीय स्टार्टअप में होने वाले अधिकांश निवेश मॉरीशस के रास्ते किए जाते हैं, क्योंकि मॉरीशस के साथ दोहरे कर से बचाव की संधि है। यानी मॉरीशस से आने वाला निवेश कर मुक्त है, लेकिन अमेरिका से आने वाला नहीं।

दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में स्थापित हुए, तो उसके विशिष्ट कारण रहे हैं। सिलिकॉन वैली में वे सब सहुलियतें और तत्व मौजूद हैं, जो किसी भी स्टार्टअप को सफल बनाते हैं। वहां कोई कंपनी स्थापित करना एक या दो दिन में संभव है और कारोबार न चल पाने की स्थिति में कंपनी को बंद करना भी बहुत आसान है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने इसी संदर्भ में कहा है कि स्टार्टअप नीति के तहत कंपनियों का पंजीकरण, निर्माण और बंदी को अब आसान बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री की स्टार्टअप नीति की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें इसमें कितना सक्रिय योगदान करती हैं? अधिकांश राज्य सरकारें बड़े उद्योगों को अपने राज्यों में बड़े निवेश के लिए आकर्षित करती रहती हैं। स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन और मदद देने में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने अच्छे प्रयास किए हैं, जिनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम प्रमुख हैं। इनकी देखा-देखी अब अन्य राज्य सरकारें भी उत्साहित होकर स्टार्टअप नीतियां बना रही हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की राज्य सरकारों के नाम उल्लेखनीय हैं।

एनडीए सरकार द्वारा धूमधाम के साथ विज्ञान भवन में स्टार्टअप नीति की घोषणा सराहनीय है। अगले कुछ महीनों में इस नीति पर स्टार्टअप उद्यमी अपने विचार और सुझाव जरूर रखेंगे। भारत में सिलिकॉन वैली जैसा सहयोगी इको-सिस्टम बनाने की कल्पना भी बहुत अच्छी है। देखना यह है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली स्टार्टअप को क्या रियायतें दे पाते हैं? यह तय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमें उद्यमिता क्रांति और इनोवेशन की तरफ तेजी से बढ़ना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)